भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-3633**
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

**एनआईआरएफ रैंकिंग में उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रगति**

**†3633. श्री बलराम नाइक पोरिका:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में रैंक प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रगति का ब्यौरा क्या हैतथा उनकी वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;
(ख) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) तथा केंद्रीयविश्वविद्यालयों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनकी प्रस्तावित समय-सीमा एवं लागत में हुई वृद्धि काब्यौरा क्या है; और
(ग) विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कौशल-एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम सेरोजगार सृजन हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार पर बल देती है, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, अवसंरचनाकी गुणवत्ता में सुधार करना, प्रभावी और गुणात्मक शिक्षक प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को भारत सरकार द्वारा वर्ष2015 में भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों की वार्षिक रैंकिंग (जिसे इंडिया रैंकिंगकहा जाता है) के लिए शुरू किया गया था, ताकि शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। इन रैंकिंग की पद्धति पांच व्यापक मापदंडों पर आधारित है जो "शिक्षण, अधिगम और संसाधन," "अनुसंधान और व्यावसायिक पद्धितयां," "स्नातक परिणाम," "पहुंच और समावेशिता," और "सहकर्मी धारणा"हैं । एनआईआरएफ के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या वर्ष 2021 में 6,272 से बढ़कर वर्ष2025 में 14,163 हो गई। एनआईआरएफ में भाग लेने वाले विशिष्टसंस्थानों की संख्या वर्ष2021-2025 के दौरान 4,030 से बढ़कर 7,692 हो गई।

एनआईआरएफ की शुरुआत के बाद से, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में शामिल होने वाले संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह संख्या वर्ष 2015 की क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में 11 संस्थानों से बढ़कर वर्ष 2027 की क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में 52 संस्थानों तक पहुँच गई है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में अनेक पहलों को संस्थागत रूप दिया गया है। भारत सरकार राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) योजना के तहत तीन घटकों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिनमें "चयनित राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता का संवर्धन", "विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान" और "बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू)" शामिल हैं, ताकि उच्च शिक्षा में सुधार किया जा सके।

इसके अलावा, विश्व स्तरीय संस्थान योजना, जिसे प्रतिष्ठित संस्थान (आईओई) योजना के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष2017 में शुरू की गई थी ताकि शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में बहुत अधिक स्वायत्तता वाले संस्थानों की एक विशिष्ट श्रेणी बनाई जा सके ताकि उन्हें एक उचित समय अवधि में विश्व स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभरने में सक्षम बनाया जा सके।

भारत सरकार ने वर्ष2014 से 43 नए प्रमुख संस्थान स्थापित किए हैं जिनमें सात आईआईटी, आठ केंद्रीय विश्वविद्यालय और 9 आईआईएम शामिल हैं। हाल ही में, फरवरी 2026 में आईआईएम गुवाहाटी को 22वें आईआईएम के रूप में उद्घाटित किया गया था। संस्थान वर्तमान में असम के कामरूप जिले में अपने ट्रांजिट कैंपस से संचालित हो रहा है। इसके विकास में सहायता करने के लिए, सरकार ने अस्थायी कैंपस स्थापित करने, स्थायी सुविधा का निर्माण शुरू करने और इसके पहले पांच वर्षों के दौरान सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए ₹555 करोड़ आवंटित किए हैं।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापितपांच नए आईआईटी के अनुसंधान पार्क का निर्माण सहित,शैक्षणिक एवं अवसंरचनाक्षमता का विस्तार का अनुमोदन दिया है, जिसकी कुल परिव्यय मई, 2025 में 11,828.79 करोड़ रुपये थी।

स्कूलों और कॉलेजों में उद्योग की आवश्यकताओं के साथ कौशल-एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक पहल की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

- स्कूली पाठ्यक्रमों को उन्नत करने के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के सहयोग से कक्षा 3 से 8 तक के शिक्षकों और छात्रों के लिए कम्प्यूटेशनल सोच और एआई पाठ्यक्रम के संसाधन तैयार किए हैं।
- शिक्षकों की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता विकसित करने के लिए, एनसीईआरटी ने एआई पर प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन करने पर ध्यान केंद्रित प्रयास किए हैं, जिससे इन कार्यक्रमों के माध्यम से 96,000 से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इसी तरह, सीबीएसई शिक्षण, अधिगमऔर मूल्यांकन में एआई उपकरणों के अनुप्रयोग के साथ-साथ शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में उनकी प्रासंगिकता के प्रति शिक्षकों को सुग्राही बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्षों में, 1234 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के 64775 शिक्षकों को लाभ हुआ है।

- यूजीसी ने भी रोजगार क्षमता में सुधार, शोध के प्रति रुचि विकसित करने और उभरती प्रौद्योगिकियों से परिचित कराने के लिए "अवर स्नातक छात्रों के लिए इंटर्नशिप/रिसर्च इंटर्नशिप के दिशा-निर्देश" शुरू किए हैं।
- इसके अलावा, यूजीसी ने उद्योग द्वारा आवश्यक कौशल को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए "अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) प्रदान करने के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों के दिशा-निर्देश" तैयार किए हैं।
- छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) जारी किया गया है, जो शिक्षा में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने में सक्षम बनाता है, जिसमें कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 50% के संचय का प्रावधान है।
- एआईसीटीई समय-समय पर शिक्षा जगत, उद्योग, व्यावसायिक निकायों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के परामर्श से अपने मॉडल पाठ्यक्रम को संशोधित करता है ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा साइंस (डीएस), मशीन लर्निंग (एमएल), साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों सहित तकनीकी विषयों में उद्योग की आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के साथ संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।
- एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा में कौशल विकास को शामिल करके इसे सक्रिय रूप से सुदृढ़ कर रहा है। यह उद्योगों और संस्थानों के साथ साझेदारी करके नियमित पाठ्यक्रम के साथ संरेखित ऑनलाइन कौशल पाठ्यक्रम, साथ ही कौशल-केंद्रित कार्यक्रम, अनिवार्य इंटर्नशिप और व्यावसायिक डिग्री प्रदान करता है।
- एआईसीटीई ने इंटर्नशिप को तकनीकी शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया है ताकि छात्रों को व्यावहारिक उद्योग अनुभव प्रदान किया जा सके और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाई जा सके।
- शिक्षा मंत्रालय युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग के सहयोग से कार्य-आधारित प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) लागू करता है।
- इसके अलावा, उद्योग-शिक्षा जगत के संबंधों को सुदृढ़ करने और शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने प्रमुख उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह प्लेटफॉर्म 89 उद्योगों के सहयोग से 15 क्षेत्रों में 500 से अधिक रोजगार-केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

*****